भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4356
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नेफेड द्वारा सोयाबीन की खरीद

4356. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उस्मानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से नेफेड के अंतर्गत सोयाबीन खरीद हेतु कितने किसानों ने पंजीकरण किया था;

(ख) क्या नेफेड सभी पंजीकृत किसानों से सोयाबीन नहीं खरीद पा रहा है और नेफेड द्वारा कितने किसानों से सोयाबीन की खरीद की गई;

(ग) क्या ऐसे पंजीकृत किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित किया गया है, जिनसे सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को किस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा;

(ङ) किसानों को लाभ पहुंचाने और उन्हें सोयाबीन का अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन पंजीकृत किसानों को बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे नेफेड सोयाबीन नहीं खरीदता था?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): खरीफ 2024 में, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत सोयाबीन खरीद हेतु उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 65,044 किसानों को पंजीकृत किया। दिनांक 15.10.2024 से 06.02.2025 तक की खरीद अवधि के दौरान, नेफेड ने 32,947 किसानों से सोयाबीन की खरीद की। खरीद अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में निर्दिष्ट खरीद केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से प्राप्त आवक के अनुसार सोयाबीन की खरीद की गई।

(ग) से (च): खरीफ 2024-25 सीज़न के दौरान, भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में पीएसएस के तहत खरीद के लिए 14,13,270 मीट्रिक टन सोयाबीन की स्वीकृति प्रदान की थी। राज्य में स्वीकृत मात्रा में से, पूर्व-पंजीकृत किसानों से नेफेड ने 8,35,757 मीट्रिक टन और एनसीसीएफ ने 2,84,257 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की। सभी पंजीकृत किसानों को कवर करने के लिए, 90 दिनों (दिनांक 15.10.2024 से) की निर्धारित खरीद अवधि को दो बार बढ़ाया गया था, अर्थात दिनांक 13.01.2025 से 31.01.2025 तक और तत्पश्चात दिनांक 06.02.2025 तक। पीएसएस घटक के अंतर्गत, उन पंजीकृत किसानों, जिनकी सोयाबीन की खरीद नहीं की गई थी, को बाज़ार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर की क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

*****